eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24196840

लैंगिक हिंसा और स्त्री–अस्मिता: मानवीय विमर्श के संदर्भ में एक आलोचनात्मक अध्ययन

डॉ रमाशंकर[1]
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद उ0प्र0

Received: 21 July 2026 Accepted & Reviewed: 25 October 2026, Published: 31 October 2026

Abstract

मानवीय संकटों—जैसे युद्ध, सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदा, विस्थापन, शरणार्थी संकट और महामारी—को सामान्यतः मानवीय पीड़ा, जीवन–रक्षा और राहत की दृष्टि से समझा जाता है। किंतु नारीवादी दृष्टिकोण यह प्रश्न उठाता है कि मानवीय संकट वास्तव में सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रभावित नहीं करते। व्यक्ति की लैंगिक पहचान, वर्ग, जाति, नस्ल, आयु, यौनिकता, विकलांगता, नागरिकता और सामाजिक स्थिति यह निर्धारित करती है कि संकट में उसकी असुरक्षा कितनी होगी और मानवीय सहायता तक उसकी पहुँच किस प्रकार की होगी। इस दृष्टि से मानवीय संकट केवल प्राकृतिक या आकस्मिक घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि वे पहले से मौजूद सामाजिक एवं सत्ता–संबंधों को और अधिक तीव्र कर सकते हैं। लैंगिक हिंसा इस असमानता का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियों में यौन हिंसा, बलात्कार, जबरन विवाह, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा और आर्थिक शोषण जैसी घटनाएँ बढ़ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं और विस्थापन की परिस्थितियों में भी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार मानवीय परिस्थितियों में यौन हिंसा संघर्ष के विभिन्न चरणों में घटित हो सकती है और कानून–व्यवस्था के कमजोर होने से अपराधियों को दंड से बच निकलने का अवसर मिलता है। नारीवादी मानवीय विमर्श इन परिस्थितियों में महिलाओं को केवल "पीड़ित" के रूप में देखने के बजाय उनकी Agency, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को केंद्र में रखता है। इसका उद्देश्य केवल महिलाओं को राहत प्रदान करना नहीं, बल्कि उन पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देना भी है जो हिंसा और असमानता को जन्म देती हैं। यह शोध–पत्र इसी प्रश्न की आलोचनात्मक पड़ताल करता है कि नारीवादी दृष्टिकोण मानवीय विमर्श को किस प्रकार पुनर्परिभाषित करता है और लैंगिक हिंसा से निपटने के लिए मानवीय संस्थाओं की पारंपरिक कार्यप्रणाली में किस प्रकार के परिवर्तन आवश्यक हैं।

प्रमुख शब्द: नारीवाद, मानवीय विमर्श, लैंगिक हिंसा, पितृसत्ता, युद्ध, विस्थापन, अंतर्विभाजकता, महिला सशक्तीकरण, मानवीय सहायता,

Introduction

मानवीय विमर्श आधुनिक विश्व राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब किसी समाज में युद्ध, प्राकृतिक आपदा, अकाल, महामारी, राजनीतिक हिंसा अथवा बड़े पैमाने पर विस्थापन की स्थिति उत्पन्न होती है, तब अंतरराष्ट्रीय समुदाय, सरकारें, गैर–सरकारी संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएँ मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय होती हैं। इस सहायता का प्रमुख उद्देश्य जीवन की रक्षा, भोजन एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, सुरक्षित आश्रय, स्वच्छ जल, सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना होता है। परंतु मानवीय सहायता की यह पारंपरिक समझ अक्सर "मानव" को एक समान और लैंगिक रूप से तटस्थ श्रेणी के रूप में प्रस्तुत करती है। नारीवादी विचारधारा इसी बिंदु पर मानवीय

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24196840

विमर्श की आलोचना करती है। नारीवादी प्रश्न यह है कि यदि संकट से प्रभावित सभी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं है, तो उन्हें समान रूप से प्रभावित मानकर बनाई गई नीतियाँ वास्तव में कितनी न्यायपूर्ण हो सकती हैं? मानवीय संकटों में लैंगिक असमानता कोई आकस्मिक घटना नहीं है। संकट से पहले मौजूद सामाजिक संरचनाएँ संकट के दौरान नए रूपों में सामने आती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी समाज में महिलाओं की सार्वजनिक निर्णय–प्रक्रिया में भागीदारी पहले से सीमित है, तो राहत और पुनर्वास की योजनाएँ बनाते समय उनकी आवाज और भी कम सुनी जा सकती है। इसी प्रकार यदि महिलाओं की आर्थिक निर्भरता अधिक है, तो विस्थापन या आजीविका के विनाश का प्रभाव उनके ऊपर अधिक गंभीर हो सकता है। इसीलिए नारीवादी मानवीय दृष्टिकोण राहत की राजनीति को सत्ता की राजनीति से जोड़ता है। वह पूछता है कि सहायता कौन देता है, किसके लिए देता है, किसकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है और निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहती है।

वर्तमान मानवीय व्यवस्था में लैंगिक समानता को शामिल करने के लिए अनेक संस्थागत प्रयास हुए हैं। IASC Gender Handbook मानवीय कार्यक्रमों में महिलाओं, लड़कियों, पुरुषों और लड़कों की अलग–अलग आवश्यकताओं, क्षमताओं और प्राथमिकताओं को पहचानने तथा महिलाओं के नेतृत्व और भागीदारी को बढ़ाने पर बल देता है। आलोचनात्मक शोध यह दर्शाता है कि केवल "Gender Mainstreaming" पर्याप्त नहीं है; आवश्यकता संस्थागत संस्कृति, सत्ता–संबंधों और निर्णय–प्रक्रिया में गहरे परिवर्तन की है।

नारीवादी दृष्टिकोण: अवधारणा और विकास– नारीवाद केवल महिलाओं के अधिकारों की मांग करने वाला आंदोलन नहीं है। व्यापक अर्थ में यह उन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचनाओं की आलोचना है जिनमें शक्ति और संसाधनों का वितरण लैंगिक आधार पर असमान होता है। नारीवादी विचारधारा का मूल प्रश्न है—सत्ता किसके पास है और उस सत्ता का निर्माण किस प्रकार होता है? पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत में "व्यक्ति" को प्रायः एक सार्वभौमिक और तटस्थ श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया गया। नारीवादी चिंतकों ने दिखाया कि यह "सार्वभौमिक व्यक्ति" अक्सर पुरुष अनुभवों को सामान्य अनुभव मानता है। परिणामस्वरूप महिलाओं के अनुभवों को निजी, घरेलू या गौण क्षेत्र में सीमित कर दिया जाता है। नारीवादी अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत ने इस आलोचना को अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक विस्तारित किया। युद्ध, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, शांति और मानवीय हस्तक्षेप जैसी अवधारणाओं को भी लैंगिक दृष्टि से देखा जाने लगा।

उदाहरण के लिए, युद्ध में सैनिकों को सक्रिय राजनीतिक अभिनेता और महिलाओं को केवल नागरिक या पीड़ित के रूप में देखना एक लैंगिक विभाजन को बनाए रखता है। वास्तव में महिलाएँ युद्ध के दौरान लड़ाकू, शांति–निर्माता, राहतकर्मी, राजनीतिक कार्यकर्ता, शरणार्थी और समुदाय की नेतृत्वकर्ता जैसी अनेक भूमिकाएँ निभाती हैं।

पितृसत्ता और मानवीय संकट– नारीवादी विश्लेषण में पितृसत्ता एक केंद्रीय अवधारणा है। पितृसत्ता ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को परिवार, समुदाय, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्थागत संरचनाओं में अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त होती है। मानवीय संकट पितृसत्ता को समाप्त नहीं करते; कई बार वे उसे और मजबूत कर देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी संघर्ष के कारण परिवार विस्थापित होता है। भोजन और

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24196840

संसाधनों की कमी होने पर परिवार के पुरुष सदस्य बाहर काम करने जाते हैं, जबकि महिलाओं पर बच्चों, बुजुर्गों और घरेलू देखभाल का अतिरिक्त भार आ सकता है। यदि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पहले से सीमित है, तो संकट के दौरान उनकी निर्भरता बढ़ जाती है।

इसी प्रकार राहत शिविरों में पर्याप्त प्रकाश, सुरक्षित शौचालय, अलग स्नान क्षेत्र या सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था न होने पर महिलाओं और लड़कियों के लिए हिंसा का जोखिम बढ़ सकता है। इस प्रकार नारीवादी दृष्टिकोण यह बताता है कि मानवीय संकट का प्रभाव केवल "आपदा" की प्रकृति से निर्धारित नहीं होता, बल्कि समाज में पहले से मौजूद सत्ता–संबंधों से भी निर्धारित होता है।

लैंगिक हिंसा और मानवीय संकट– लैंगिक हिंसा का अर्थ ऐसी हिंसा से है जो किसी व्यक्ति को उसके लिंग या लैंगिक पहचान के आधार पर प्रभावित करती है। इसमें शारीरिक, यौन, मानसिक, आर्थिक और संरचनात्मक हिंसा शामिल हो सकती है। मानवीय संकटों में इसके अनेक रूप दिखाई देते हैं: यौन हिंसा और बलात्कार, घरेलू हिंसा, जबरन विवाह, बाल विवाह, मानव तस्करी, यौन शोषण, आर्थिक शोषण, लैंगिक उत्पीड़न, जबरन गर्भधारण, प्रजनन संबंधी अधिकारों पर नियंत्रण।

•यौन एवं लैंगिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा– संघर्ष की परिस्थितियों में यौन हिंसा का इस्तेमाल केवल व्यक्तिगत अपराध के रूप में नहीं बल्कि समुदायों को अपमानित करने, सामाजिक संबंधों को तोड़ने और भय पैदा करने के साधन के रूप में भी किया जा सकता है। UNFPA के अनुसार युद्ध और मानवीय संकटों में महिलाओं और किशोरियों की असुरक्षा कई कारणों से बढ़ती है, जिनमें परिवार से अलगाव, संसाधनों की खोज के लिए लंबी दूरी तय करना और कानून–व्यवस्था का कमजोर होना शामिल हैं। United Nations Population Fund. इसलिए लैंगिक हिंसा को केवल "महिलाओं की समस्या" मानना पर्याप्त नहीं है। यह सत्ता, युद्ध, सामाजिक संरचना और मानवाधिकारों का प्रश्न है।

नारीवादी दृष्टिकोण से "पीड़िता" की अवधारणा– मानवीय विमर्श में महिलाओं को अक्सर "Vulnerable Women" या "Victim" के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्तुति कुछ संदर्भों में आवश्यक हो सकती है क्योंकि महिलाओं और लड़कियों को वास्तविक सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है। लेकिन नारीवादी आलोचना यह प्रश्न उठाती है कि क्या महिला को हमेशा केवल पीड़िता के रूप में प्रस्तुत करना उसकी Agency को समाप्त नहीं करता? महिलाएँ संकटों में केवल सहायता प्राप्त करने वाली नहीं होतीं। वे स्वयं सहायता प्रदान करने वाली, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षिका, समुदाय–नेता, शांति–निर्माता और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हो सकती हैं। UN Women भी मानता है कि संकटग्रस्त महिलाएँ केवल Victims नहीं बल्कि Responders भी होती हैं और स्थानीय स्तर पर समुदायों की आवश्यकताओं को समझने तथा मानवीय प्रतिक्रिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अतः नारीवादी मानवीय दृष्टिकोण "Victimhood" के स्थान पर Agency को केंद्र में लाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि महिलाओं की Vulnerability को नकार दिया जाए। बल्कि इसका अर्थ है कि Vulnerability और Agency को एक साथ समझा जाए।

मानवीय विमर्श में Agency का महत्व– Agency का अर्थ है व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों में निर्णय लेने, कार्य करने और अपने जीवन को प्रभावित करने की क्षमता। पारंपरिक मानवीय सहायता अक्सर

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24196840

महिलाओं को सहायता की प्राप्तकर्ता मानती है। नारीवादी दृष्टिकोण उन्हें निर्णय लेने वाली राजनीतिक और सामाजिक एजेंट के रूप में देखने की मांग करता है। यदि किसी राहत शिविर में महिलाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, तो यह देखना भी आवश्यक है कि भोजन के वितरण का निर्णय कौन ले रहा है। यदि महिलाओं की वास्तविक आवश्यकताओं पर उनसे बातचीत नहीं की जाती, तो राहत कार्यक्रम Gender&Sensitive होने का दावा तो कर सकता है, लेकिन वह वास्तव में Participatory नहीं होगा। इसी कारण महिला–नेतृत्व वाले स्थानीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। UN Women की मानवीय रणनीति महिलाओं की आवाज, नेतृत्व और Agency को मानवीय कार्रवाई का महत्वपूर्ण आधार मानती है।

Gender Mainstreaming और उसकी सीमाएँ– पिछले कुछ दशकों में मानवीय संस्थाओं में Gender Mainstreaming को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ है कि किसी कार्यक्रम को बनाते समय महिलाओं और पुरुषों पर उसके अलग–अलग प्रभावों को ध्यान में रखा जाए।

यह एक महत्वपूर्ण प्रगति है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं।

पहली सीमा यह है कि Gender Mainstreaming कभी–कभी केवल प्रशासनिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है। उदाहरण के लिए किसी परियोजना में महिलाओं की संख्या दर्ज कर लेना या Gender Indicator जोड़ देना अपने–आप में Gender Justice सुनिश्चित नहीं करता।

दूसरी सीमा यह है कि संस्थागत संरचनाएँ स्वयं पितृसत्तात्मक हो सकती हैं। यदि निर्णय लेने वाले पदों पर मुख्यतः पुरुष हों, तो महिलाओं के बारे में बनाई जाने वाली नीतियाँ उनकी वास्तविक आवश्यकताओं से दूर हो सकती हैं।

2023 के एक अध्ययन ने मानवीय क्षेत्र में Gender Mainstreaming का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि यह अक्सर संस्थागत प्रक्रियाओं को बदलने तक सीमित रहती है, जबकि महिलाओं और पुरुषों के लिए वास्तविक परिणामों तथा संस्थागत संस्कृति के परिवर्तन पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए आवश्यकता Gender Mainstreaming से आगे बढ़कर Gender Transformation की है।

अंतर्विभाजकता और मानवीय विमर्श– नारीवादी दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण विकास Intersectionality की अवधारणा है। इसे विशेष रूप से Kimberlé Crenshaw के कार्य से जोड़ा जाता है। Intersectionality यह बताती है कि लैंगिक पहचान अकेले किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित नहीं करती। महिला होने के साथ–साथ कोई व्यक्ति गरीब, दलित, आदिवासी, प्रवासी, शरणार्थी, विकलांग, वृद्ध, या किसी अन्य हाशिए के समूह से संबंधित हो सकता है। इन विभिन्न पहचानों का प्रभाव एक–दूसरे से जुड़ता है। उदाहरण के लिए, एक संपन्न शहरी महिला और एक गरीब ग्रामीण विस्थापित महिला दोनों "महिला" हैं, लेकिन मानवीय संकट में उनकी समस्याएँ समान नहीं होंगी। एक के पास डिजिटल संसाधन, आर्थिक पूँजी और सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं, जबकि दूसरी के पास इनका अभाव हो सकता है। इसीलिए एक प्रभावी मानवीय नीति को "Women" को एक समान श्रेणी मानने से बचना चाहिए। UN Women के हालिया शोध में भी मानवीय परिस्थितियों में Intersectional दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया है और यह रेखांकित किया गया है कि Gender विभिन्न समूहों —महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों, लड़कों तथा अन्य लैंगिक पहचानों—को अलग–अलग प्रभावित करता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24196840

पुरुष और पुरुषत्व: नारीवादी विमर्श का विस्तार– नारीवादी मानवीय विमर्श का अर्थ केवल महिलाओं का अध्ययन करना नहीं है। यह पुरुषत्व की सामाजिक संरचना का भी विश्लेषण करता है। युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियों में पुरुषों को अक्सर "योद्धा", "रक्षक" या "कमाऊ सदस्य" की भूमिका में देखा जाता है। यह सामाजिक अपेक्षा पुरुषों पर भी दबाव डाल सकती है। कुछ पुरुष और लड़के भी यौन हिंसा के शिकार होते हैं, लेकिन सामाजिक कलंक और पुरुषत्व की रूढ़ धारणाओं के कारण वे हिंसा की रिपोर्ट करने से बच सकते हैं।

इसलिए Gender–Based Violence को केवल "Violence Against Women" तक सीमित कर देना भी विश्लेषणात्मक रूप से अपर्याप्त हो सकता है। Chris Dolan ने मानवीय क्षेत्र में Gender Binary से आगे बढ़ने और यह समझने की आवश्यकता पर बल दिया है कि महिलाएँ और लड़कियाँ लैंगिक हिंसा की एकमात्र पीड़ित नहीं हैं। इससे मानवीय विमर्श अधिक समावेशी बन सकता है, हालांकि महिलाओं के विरुद्ध संरचनात्मक हिंसा की विशिष्टता को अदृश्य किए बिना।

युद्ध, राष्ट्रवाद और महिलाओं के शरीर की राजनीति– नारीवादी अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत ने युद्ध में महिलाओं के शरीर की राजनीतिक भूमिका पर विशेष ध्यान दिया है। युद्ध के दौरान महिलाओं के शरीर को समुदाय, संस्कृति और राष्ट्र की "इज्जत" के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस स्थिति में महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा केवल व्यक्ति पर हमला नहीं रह जाती बल्कि पूरे समुदाय पर नियंत्रण स्थापित करने का माध्यम बन जाती है। इस प्रकार बलात्कार और अन्य यौन हिंसा को युद्ध की रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जाना Gender और Power के गहरे संबंध को दिखाता है। लेकिन नारीवादी विश्लेषण यह भी सावधान करता है कि महिलाओं को राष्ट्र या समुदाय की "इज्जत" का प्रतीक मानना स्वयं पितृसत्तात्मक व्यवस्था का हिस्सा है। महिला की गरिमा इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए कि वह परिवार या राष्ट्र की "इज्जत" का प्रतिनिधित्व करती है; वह एक स्वतंत्र मानव अधिकार धारक है।

शरणार्थी और विस्थापित महिलाओं का प्रश्न– विस्थापन मानवीय संकटों का महत्वपूर्ण आयाम है। घर, जमीन, सामाजिक नेटवर्क और आर्थिक संसाधनों से अलग होना महिलाओं के लिए अनेक नए जोखिम पैदा कर सकता है। शरणार्थी शिविरों और अस्थायी बस्तियों में: सुरक्षा का अभाव, सुरक्षित शौचालयों की कमी, निजी स्थान का अभाव, भोजन और ईंधन प्राप्त करने में जोखिम, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, आर्थिक निर्भरता, यौन शोषण, तस्करी, घरेलू हिंसा जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

लेकिन यहां भी महिलाओं को केवल "बेचारी शरणार्थी" के रूप में देखना उचित नहीं है। विस्थापित महिलाएँ सामुदायिक नेटवर्क बनाती हैं, आजीविका विकसित करती हैं, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करती हैं तथा राहत गतिविधियों में नेतृत्व करती हैं। इसलिए मानवीय सहायता का उद्देश्य केवल महिलाओं को सुरक्षित स्थान देना नहीं बल्कि उन्हें संसाधनों और निर्णय लेने की शक्ति उपलब्ध कराना भी होना चाहिए।

मानवीय संगठनों की भूमिका– UN Women की मानवीय रणनीति में दो महत्वपूर्ण आयाम दिखाई देते हैं—पहला, मानवीय समन्वय और कार्यान्वयन में Gender Commitments के प्रति Accountability को मजबूत करना; दूसरा, संकटग्रस्त महिलाओं और लड़कियों के लिए Protection तथा livelihood Support को मजबूत करना। इससे मानवीय विमर्श में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है: महिलाओं को केवल

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24196840

सहायता की प्राप्तकर्ता न मानकर उन्हें नेतृत्व और निर्णय–प्रक्रिया में शामिल करना। इसी प्रकार Safe Spaces, Psychosocial Support, livelihood Assistance, Education और Gender&Based Violence Response जैसी गतिविधियाँ महिलाओं की सुरक्षा और Agency दोनों को मजबूत कर सकती हैं। हालांकि, इन कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों को कितना समझते हैं और स्थानीय महिला संगठनों के साथ कितना समानतापूर्ण सहयोग करते हैं।

स्थानीय महिला संगठनों का महत्व– नारीवादी मानवीय विमर्श का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है—localization किसी बाहरी अंतरराष्ट्रीय संस्था के लिए स्थानीय समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं को समझना कठिन हो सकता है। इसके विपरीत स्थानीय महिला संगठन समुदाय की भाषा, सामाजिक संरचना, शक्ति–संबंध और जोखिमों को बेहतर समझते हैं।

इसलिए मानवीय सहायता का लोकतांत्रिकीकरण केवल महिलाओं को कार्यक्रम में शामिल करने से नहीं होगा। आवश्यक है कि स्थानीय महिला संगठनों को वित्तीय संसाधन, निर्णय लेने की शक्ति और दीर्घकालिक संस्थागत समर्थन भी दिया जाए। UN Women के 2024 के मानवीय कार्य के अनुसार संस्था ने संकट और विस्थापन से प्रभावित अनेक संदर्भों में स्थानीय महिला–नेतृत्व वाले संगठनों की भागीदारी और प्रभाव को मजबूत करने पर काम किया। यह दृष्टिकोण मानवीय सहायता की "Top&Down" संरचना को चुनौती देता है।

मानवीय सिद्धांत और नारीवादी आलोचना – मानवीय क्षेत्र में neutrality, impartiality और Independence जैसे सिद्धांत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन नारीवादी आलोचना यह पूछती है कि क्या Neutrality का अर्थ सामाजिक अन्याय के प्रति भी तटस्थ रहना होना चाहिए? यदि किसी समाज में महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, राजनीतिक भागीदारी या स्वतंत्र आवागमन से व्यवस्थित रूप से वंचित किया जाता है, तो केवल "हम सभी को समान सहायता देंगे" कहना पर्याप्त नहीं हो सकता। क्योंकि समान सहायता हमेशा समान परिणाम नहीं देती।

2024 में प्रकाशित एक आलोचनात्मक अध्ययन ने मानवीय सिद्धांतों और Gender Justice के बीच इसी तनाव की चर्चा की तथा यह तर्क दिया कि पितृसत्तात्मक शक्ति–संबंधों को अनदेखा करना कभी–कभी Gender Justice के प्रयासों को कमजोर कर सकता है। इसलिए नारीवादी दृष्टिकोण Neutrality को समाप्त करने की मांग नहीं करताय बल्कि वह Neutrality की ऐसी व्याख्या की मांग करता है जिसमें सामाजिक असमानता को पहचानने की क्षमता हो।

मीडिया और मानवीय विमर्श में महिलाओं का प्रतिनिधित्व– मानवीय संकटों की मीडिया प्रस्तुति भी लैंगिक होती है। समाचार और अभियान सामग्री में महिलाओं को अक्सर रोती हुई, पीड़ित, असहाय और सहायता की प्रतीक्षा करती हुई दिखाया जाता है। ऐसी छवि सहायता जुटाने में प्रभावी हो सकती है, लेकिन इससे महिलाओं की Agency अदृश्य हो सकती है।

नारीवादी विमर्श इसलिए प्रतिनिधित्व के प्रश्न को महत्वपूर्ण मानता है: किसकी कहानी कही जा रही है? कौन बोल रहा है? किसकी आवाज अनुवादित या संपादित की जा रही है? किसे केवल पीड़ित के रूप में

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24196840

दिखाया जा रहा है? एक अधिक न्यायपूर्ण मानवीय संचार व्यवस्था में महिलाओं को अपनी कहानी स्वयं कहने का अवसर मिलना चाहिए।

सुरक्षा की नारीवादी अवधारणा– पारंपरिक सुरक्षा विमर्श में सुरक्षा का अर्थ प्रायः राज्य की सीमा, सेना और राजनीतिक स्थिरता से जुड़ा रहा है। नारीवादी सुरक्षा अध्ययन सुरक्षा की अवधारणा का विस्तार करता है। व्यक्ति के लिए सुरक्षा का अर्थ केवल युद्ध से बचना नहीं बल्कि: हिंसा से सुरक्षा,भोजन की उपलब्धता,स्वास्थ्य,शिक्षा, सम्मान, आर्थिक स्वतंत्रता, यौन और प्रजनन अधिकार, राजनीतिक भागीदारी भी है। इस दृष्टि से मानवीय सुरक्षा और नारीवादी सुरक्षा के बीच महत्वपूर्ण संबंध स्थापित होता है। यदि कोई महिला युद्ध से तो बच गई लेकिन उसे घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा नहीं मिली, तो क्या हम उसे पूरी तरह सुरक्षित कह सकते हैं? नारीवादी दृष्टिकोण का उत्तर है—नहीं।

नारीवादी मानवीय विमर्श की प्रमुख चुनौतियाँ– यद्यपि नारीवादी दृष्टिकोण ने मानवीय क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, फिर भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं।

प्रतीकात्मक भागीदारी– कई बार महिलाओं को बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल तो किया जाता है, लेकिन वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति उनके पास नहीं होती।

वित्तीय असमानता – महिला–नेतृत्व वाले स्थानीय संगठनों को अंतरराष्ट्रीय संगठनों की तुलना में कम संसाधन मिल सकते हैं।

संकट की तात्कालिकता – मानवीय संस्थाएँ अक्सर जीवन बचाने की तत्काल आवश्यकता पर केंद्रित होती हैं। परिणामस्वरूप सामाजिक संरचना और लैंगिक सत्ता–संबंधों में दीर्घकालिक परिवर्तन को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिलती।

सांस्कृतिक संवेदनशीलता की समस्या – Gender Equality के प्रश्न पर काम करते समय स्थानीय संस्कृति और समुदाय की संवेदनशीलताओं को समझना आवश्यक है। लेकिन "संस्कृति" का इस्तेमाल महिलाओं के अधिकारों को नकारने के लिए भी किया जा सकता है।

संस्थागत पितृसत्ता – मानवीय संस्थाएँ स्वयं भी लैंगिक असमानता से मुक्त नहीं हैं। इसलिए बाहरी समाज में Gender Equality की वकालत करने वाली संस्थाओं को अपने आंतरिक संगठनात्मक ढाँचे की भी समीक्षा करनी चाहिए।

भविष्य के लिए सुझाव – नारीवादी मानवीय विमर्श को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्न उपाय महत्वपूर्ण हैं:

- मानवीय जरूरतों का Gender और Intersectional Assessment अनिवार्य किया जाए।
- महिलाओं की सुरक्षित और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- स्थानीय महिला संगठनों को सीधे और दीर्घकालिक वित्तीय सहयोग दिया जाए।
- Gender–Based Violence की रोकथाम को केवल Emergency Response न मानकर दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाया जाए।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24196840

- राहत शिविरों और विस्थापन केंद्रों की डिजाइन में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।
- महिलाओं के लिए आजीविका और आर्थिक स्वतंत्रता के कार्यक्रम बढ़ाए जाएँ।
- मानसिक स्वास्थ्य और Psychosocial Support को Gender–Sensitive बनाया जाए।
- पुरुषों और लड़कों को भी Gender–Transformative कार्यक्रमों में शामिल किया जाए।
- मानवीय संस्थाओं में लैंगिक समानता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
- महिलाओं को स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय नीति–निर्माण में नेतृत्व की भूमिका दी जाए।
- "Victim" की छवि के स्थान पर Women*s Agency और Resilience को मान्यता दी जाए।
- मानवीय सहायता के मूल्यांकन में केवल लाभार्थियों की संख्या नहीं, बल्कि Empowerment और Decision–Making जैसे परिणाम भी शामिल किए जाएँ।

निष्कर्ष– नारीवादी दृष्टिकोण ने मानवीय विमर्श की पारंपरिक समझ को महत्वपूर्ण रूप से चुनौती दी है। इसने यह स्पष्ट किया है कि "मानव" कोई लैंगिक रूप से तटस्थ श्रेणी नहीं है और मानवीय संकट सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रभावित नहीं करते। युद्ध, विस्थापन, आपदा और सामाजिक अस्थिरता पहले से मौजूद लैंगिक असमानताओं को अधिक गहरा कर सकती हैं। लैंगिक हिंसा इस वास्तविकता का सबसे गंभीर उदाहरण है। महिलाओं और लड़कियों को यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण, जबरन विवाह, तस्करी और अन्य प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन नारीवादी दृष्टिकोण का महत्व केवल इन जोखिमों की पहचान करने में नहीं है। इसकी वास्तविक शक्ति इस बात में है कि यह महिलाओं को केवल पीड़ित के रूप में देखने से इनकार करता है।

मानवीय संकटों में महिलाएँ सहायता प्राप्त करने वाली ही नहीं बल्कि सहायता देने वाली, समुदाय की नेता, शांति–निर्माता और राजनीतिक एजेंट भी होती हैं। इसलिए मानवीय कार्रवाई में महिलाओं की Agency, Leadership और Participation को केंद्र में रखना आवश्यक है। इसी संदर्भ में Gender Mainstreaming एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, लेकिन यह अपने–आप में पर्याप्त नहीं है। यदि मानवीय संस्थाओं की संरचना, वित्तीय व्यवस्था और निर्णय–प्रक्रिया में सत्ता का असमान वितरण बना रहता है, तो Gender Mainstreaming केवल प्रशासनिक प्रक्रिया बनकर रह सकती है। आवश्यकता ऐसे Transformative Humanitarianism की है जो पितृसत्ता, असमानता और हिंसा की संरचनात्मक जड़ों को भी संबोधित करे।

Intersectionality इस दिशा में एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक उपकरण उपलब्ध कराती है। महिला कोई एक समान सामाजिक श्रेणी नहीं है। जाति, वर्ग, नस्ल, आयु, विकलांगता, नागरिकता, यौनिकता और अन्य सामाजिक पहचानें लैंगिक अनुभव को प्रभावित करती हैं। इसलिए मानवीय प्रतिक्रिया भी इन विभिन्न पहचानों के अंतर्संबंधों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए। अंततः नारीवादी मानवीय विमर्श का लक्ष्य केवल "महिलाओं के लिए बेहतर राहत" नहीं है। इसका व्यापक लक्ष्य ऐसी मानवीय व्यवस्था का निर्माण है जिसमें प्रभावित समुदाय अपनी सहायता और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में वास्तविक निर्णयकर्ता हों; स्थानीय महिलाओं के संगठन संसाधनों और सत्ता तक पहुँच रखते हों; लैंगिक हिंसा को संकट का अनिवार्य परिणाम न माना

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 10, October 2026 DOI- https://doi.org/10.5281/zenodo.24196840

जाए; और महिलाओं को असहाय पीड़ित के बजाय अधिकार–संपन्न नागरिक तथा परिवर्तनकारी एजेंट के रूप में देखा जाए। इस अर्थ में नारीवादी दृष्टिकोण मानवीय विमर्श को अधिक संवेदनशील ही नहीं, बल्कि अधिक न्यायपूर्ण, सहभागी और मानव–केंद्रित बनाता है। वर्तमान वैश्विक संकटों की जटिलता को देखते हुए यह दृष्टिकोण मानवीय कार्रवाई के लिए वैकल्पिक विचारधारा भर नहीं, बल्कि एक आवश्यक नैतिक और राजनीतिक दिशा के रूप में सामने आता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आंबेडकर, बी. आर. (2014). जाति का विनाश. सम्यक प्रकाशन।

2. अग्रवाल, नीरजा. (2018). नारी विमर्श और समकालीन समाज. वाणी प्रकाशन।

3. जैन, प्रभा. (2006). स्त्री विमर्श भारतीय परिप्रेक्ष्य. राजकमल प्रकाशन।

4. देसाई, नीरा, एवं पटेल, वीना. (1987). भारतीय महिलाओं की स्थिति. नेशनल बुक ट्रस्ट।

5. पांडेय, मैनेजर. (2005). साहित्य और इतिहास दृष्टि. वाणी प्रकाशन।

6. प्रभा खेतान. (2004). उपनिवेश में स्त्री. राजकमल प्रकाशन।

7. महादेवी वर्मा. (2011). श्रृंखला की कड़ियाँ. लोकभारती प्रकाशन।

8. शर्मा, रमणिका. (2009). स्त्री विमर्श और साहित्य. सामयिक प्रकाशन।

9. सिंह, सविता. (2012). स्त्री अस्मिता और विमर्श. अनामिका प्रकाशन।

10. भारतीय संविधान. (2020). भारत का संविधान. भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय।

11. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2013). महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रिपोर्ट. भारत सरकार।